



TRUE VALUE

MARUTI SUZUKI

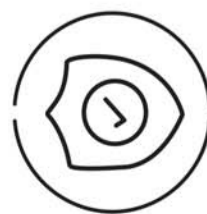
वाइड रेंज के साथ बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी सिर्फ TRUE VALUE पे



CELEBRATING

50 LAKH

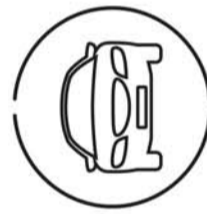
HAPPY FAMILIES



376 क्वालिटी
चेक पॉइंट्स



3 फ्री सर्विस और
1 साल तक की वारंटी*



वेरिफाइड
कार हिस्ट्री*



अधिक
जानने के लिए
स्कैन करें

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है।

UDAIPUR: SUKHER, 200 FEET ROAD, SUKHER BYE PASS, KHELGAON ROAD, NEAR BHERAVGARH RESORT, UDAIPUR, TECHNOL MOTORS: 9530396820, 8112266227, 9530396861 | S-140,
MADRI INDUSTRIAL AREA, UDAIPUR, NAVNEET MOTORS: 7230016838, 9929140770, 7597349534 | BANSWARA: THIKARIA DAHOD ROAD, BANSWARA, NAVNEET MOTORS: 7665887333.

कर्नाटक में कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने 50 विधायकों को पचास-पचास करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र ने कहा, बिना प्रमाण दिए ऐसे आरोप लगाना बचकाना राजनैतिक बयान है

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया के एक दावे ने कर्नाटक के राजनीतिक वातावरण में तूफान ला दिया है जो भी ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रु. की पेशकश कर रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को एक जनसभा में दिए गए इस बयान के कारणों व प्रभाव को राजनैतिक विश्लेषक टायल बेल्लुन के रूप में देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल कांग्रेस महाराष्ट्र व झारखण्ड के विधानसभा चुनावों में कर रही है इनमें कर्नाटक की तीन विधानसभा सीटें भी शामिल हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए उन्हें सबूत देने की चुनौती दी।

लेकिन इस आरोप का अधिकृत तौर पर खंडन आने से इन पर ज्यादा यकीन हो जाएगा। खासकर भाजपा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। भाजपा कई राज्य

■ कर्नाटक में कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आरोपों का समर्थन किया और कहा, भाजपा का निर्वाचित सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाने का इतिहास रहा है।

■ शिवकुमार ने कहा, भाजपा ने कर्नाटक में ऐसा किया था और कांग्रेस-जद (एस.) गठबंधन की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने जद (एस) और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया था।

■ शिवकुमार ने मध्यप्रदेश का उदाहरण भी दिया, जहाँ, भाजपा ने ज्योतिरादित्य व उनके समर्थकों से दल-बदल करवा कर कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिरा दी थी।

■ इधर भाजपा ने कहा कि असल में सिद्धारमैया को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है वे उन पर नियंत्रण करने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।

सरकारों को साबित करके गिराया है। जिनमें कर्नाटक भी शामिल है जब कांग्रेस व जग एस्.के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया ताजिसकी वजह से कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी जिसमें कांग्रेस

सहयोगी थी। इसके बाद भाजपा ने सरकार बनाई थी।

इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी भाजपा ने यही रास्ता अपनाया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक

विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी जिससे कांग्रेस अल्पमत में आ गई और फिर ज्योतिरादित्य की मदद से भाजपा की सरकार बनी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भाजपा के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं, कि भाजपा उनकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के हरेक विधायक को पचास करोड़ रु. की पेशकश कर रही है।

सिद्धारमैया ने कहा, "सिद्धारमैया की सरकार गिराने के लिए उन्होंने कांग्रेस के 50 विधायकों में से प्रत्येक को 50 करोड़ रु. की पेशकश की है। उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों यदियुराया व बोम्मई से या फिर विपक्ष के नेता आर. अशोक या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र से? यह पैसा भाजपा नेताओं ने रिश्त से एकत्रित किया और फिर कांग्रेस विधायकों को ललचाने का असफल प्रयास किया।

सिद्धारमैया ने कहा इस बार कोई कांग्रेस विधायक नहीं माना। इन्होंने किसी भी तरह से हमारी सरकार को हटाने की (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

गौवंश तस्कर की जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में

जयपुर, 14 नवंबर। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश निवासी आदतन गौवंश तस्कर नजीम खान को, 21 अक्टूबर को मिली जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर की है। रिव्यू पिटिशन में राज्य सरकार ने आरोपों को जमानत देने वाला आदेश

■ राजस्थान सरकार ने आरोपी की जमानत के आदेश को रद्द करने का रिव्यू पिटिशन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील का वकालत नामा नहीं आने के कारण जमानत दी थी।

वापस लेकर उसे रद्द करने का आग्रह किया है।

राज्य के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान गौवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मामलों दर्ज हैं। उस पर उत्तर प्रदेश में भी गिरोह (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

फोन टैपिंग में लोकेश शर्मा ने याचिका वापस ली

जयपुर, 14 नवंबर। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान फोन टैपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोट के ओ.एस.डी. रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपनी याचिका को वापस ले लिया है। लोकेश शर्मा ने याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफ.आई.आर. को निरस्त करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर करने की गुहार की थी। इसके साथ ही मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक स्वतः हट गई है। लोकेश शर्मा की ओर से पेश

■ याचिका वापस लेने से लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर से रोक हट गई।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस की ब्राह्म ब्रांच में बयान दर्ज कराने के साथ ही सबूत भी सौंप दिए हैं। ऐसे में अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट को रद्द करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर की गुहार करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट ने 26 हजार प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश दिये

ममता बनर्जी सरकार के शिक्षा मंत्री इस स्केम में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तथा जेल में बन्द हैं

—अंजन राँय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 14 नवंबर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज, तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 26 हजार प्राइमरी स्कूल टीचरों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।

माने तृणमूल कांग्रेस सरकार और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुसीबतों का जैसे अंत ही नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक विनाशकारी निर्णय जारी किया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश अभिजित गांगुली के आदेश की पुष्टि की गई।

उच्च न्यायालय ने, राज्य के स्कूलों में की गई, 26 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले, न्यायमूर्ति गांगुली के आदेश को बरकरार रखा है।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा तथा समस्त प्रक्रिया आयोजित की थी, जिसे एक उम्मीदवार

■ ममता बनर्जी सरकार अब तक "जॉब फॉर कैश" स्केम में इन शिक्षकों को बचाने का प्रयास ही करती दिख रही है। सरकार इन सभी नियुक्ति पत्रों को रद्द कर पुनः पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष भाव से पूरी करके पुराने नियुक्तियों को रद्द करके, नई नियुक्तियों करने के आदेश को रूकवाने की पूरी कोशिश में ही रही है।

ने चुनौती दी थी। इस उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। यह बात सामने आई कि स्कूल सेवा आयोग ने ब्लैक लिस्टेड सैंडो कंपनियों के माध्यम से अपारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई थी। जस्टिस गांगुली के समक्ष प्रस्तुत प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई थीं, जैसे कि, जिन उम्मीदवारों ने अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें बाहर कर दिया गया था और उन उम्मीदवारों को लिया गया था जिन्हें एस. एस. सी. परीक्षाओं में बहुत कम अंक मिले थे। यह "जॉब फॉर कैश" घोटाला था और चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों ने

अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए रिश्त ली थी। इन प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर अदालत ने सी. बी. आई. को व्यापक जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान, सी. बी. आई. टीम शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दरवाजे पर पहुंची और उनके एक घर से करीब 60 लाख रुपये की नकदी बरामद की। शिक्षा मंत्री के घर में पाए गए इतने अधिक कैश को देख कर समस्त राज्य अर्चभित था कि, अनियमितताएँ किस हद तक हुई हैं। राज्य शिक्षा मंत्री, पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय

को और उनकी गलफिंड जेल में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इन भारी अनियमितताओं से दूरी बनाने के लिए तुरंत ही मंत्री को निष्कासित कर दिया था।

फिर भी, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए, अपरोक्ष रूप से इन चोर अनियमितताओं का समर्थन किया था, कि जिन्हें नियुक्ति दे दी गई है उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि योग्य उम्मीदवार बिना नौकरी के रहते। भारी संख्या में उम्मीदवार, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली, वो पिछले दो वर्षों से "घरने" प्रदर्शन कर रहे हैं। यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब देश में कई जगह चुनाव प्रक्रिया जारी है, ऐसे में अदालत द्वारा सरकार की भर्ती प्रक्रिया की जबरदस्त निंदा का आम जनभावना पर कुछ तो असर होगा। हाई कोर्ट के निर्णय के जवाब में ममता बनर्जी ने उन उम्मीदवारों को आश्चर्य करने कोशिश की जो बर्खास्त कर दिए (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ परिवाद में साक्ष्य पेश करने के आदेश

जयपुर, 14 नवंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय, ने शिवा समुदाय के इमाम बारागाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के मामले में हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ पेश परिवाद पर सुनवाई करते

■ शिवा समुदाय की इमाम बारागाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने का परिवाद विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ पेश हुआ है।

हुए परिवादी को 28 नवंबर को अपने साक्ष्य पेश करने को कहा है। पीठासीन अधिकारी आयुषी गौतम ने यह आदेश रियाज हुसैन के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन का संचालन फिर लटका

रेलवे सेफ्टी कमिश्नर "लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट" के बाद फिर से सुरक्षा सम्बन्धी टैस्ट करेंगे

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 14 नवम्बर। लंबे समय अनिर्णित, 272 कि.मी. लंबी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की कमप्लीशन डेट को एक बार फिर अप्रत्याशित कारणों से आगे खिसका दिया गया है। तारीख आगे करने का कारण यह संभावना है कि रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर, "लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट" करने के बाद सेफ्टी सर्टिफिकेशन टैस्ट फिर से करेंगे।

यह प्रोजेक्ट तीन दशकों से चल रहा है तथा कई बार इसकी डैडलाइन निकल चुकी है और इसकी लागत भी बहुत बढ़ गई है। इसे 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था और 2015-16 में इसकी अनुमानित लागत 25,100 करोड़ रु. दी थी, जो 2022 में बढ़कर 28,000 करोड़ हो गई थी। अधिकारियों ने संकेत दिया कि अब इसकी लागत 40,000 करोड़ रु. तक पहुंचन की उम्मीद है।

आप के महेश खींची दिल्ली के महापौर बने

नई दिल्ली, 14 नवंबर। आम आदमी पार्टी के महेश खींची दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। गुरुवार को हुए मतदान में खींची को 133 और भाजपा को 130 वोट मिले। दो पार्श्वों का वोट अवैध घोषित किया गया। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के सीट पर

■ आप पार्टी को 133 वोट मिले और भाजपा को 130 वोट मिले। कांग्रेस के 8 पार्श्वों ने मतदान का बहिष्कार किया।

पहुंचे ही सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्श्वों ने सदन में हंगामा किया। कांग्रेस पार्श्वों ने आप के मेयर पर दलितों का हक मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस के सभी 8 पार्श्वों ने सदन (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

■ लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट किसी रेल पुल की लचीली क्षमता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें पुल पर रेल की गति और वजन पर पुल की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है।

■ 272 किलोमीटर लम्बी इस रेल लाइन पर तीन दशकों से काम चल रहा है तथा इसकी लागत 25 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 40 हजार करोड़ रु. हो गई है। निकट भविष्य में भी इसके पूरे होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है।

योजना पर धीमी प्रगति है, पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो गई है। कुल 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर पर काम पूरा हो गया है और बचे हुए 63 किलोमीटर लम्बे कटरा-संगलदान सैक्शन में काम पूरे होने के करीब है।

गत वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 48 किलोमीटर लम्बे बनिहाल संगलदान सैक्शन का उद्घाटन किया था। इस लाइन की सभी 38 सुरों,

जिसमें 12.75 किलोमीटर लम्बी भारत की सबसे लम्बी सुरंग टी-49 भी शामिल है, पूरी हो चुकी है तथा 39 पुलों में से मात्र एक पर काम चल रहा है, कटरा संगलदान सैक्शन के सभी चार भाग पूरे हो गए हैं। गत वर्ष जून में भारतीय रेल्वे ने चिनाब ब्रिज पर सफल ट्रायल किया था। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है जो संगलदान और रेआसी के बीच (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

क्या राजफेड ने ऑरिगो और श्री शुभम् लॉजिस्टिक को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया कृषि उपज के भंडारण का "मूवमेंट प्लान"?

—यादवेन्द्र शर्मा—

जयपुर, 14 नवम्बर। क्या राजफेड ने ऑरिगो और श्री शुभम् लॉजिस्टिक को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि उपज के भंडारण का "मूवमेंट प्लान" बनाया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि, राजफेड ने गत 18 अक्टूबर से खरीफ की फसलें जिनमें दलहन व तिलहन शामिल हैं, को खरीदना शुरू किया और उन्हें राजस्थान राज्य भंडारण निगम के गोदामों में रखने का एक "मूवमेंट प्लान" बना लिया। जिसके बारे में कोई भी जानकारी ना तो भंडारण निगम के अफसरों को दी गई और ना ही यह प्लान बनाने से पहले उनके गोदामों की क्षमता, बीमा, सुविधा व खाली जगह के बारे में कोई जानकारी ली गई। चर्चाएँ हैं कि किसानों से सम्बंधित मूल्य पर खरीदा हुआ दलहन व तिलहन का यह भारी-भरकम स्टॉक भंडारण निगम के उन गोदामों में रखने की बात

कही जा रही है, जिनका इंश्योरेंस तक नहीं करवाया हुआ है। ऐसे में यहाँ अगर कृषि उपज का जो खराबा होगा, उसके लिए भंडारण निगम ही जिम्मेदार होगा। जबकि निगम ने करीब 60 प्रतिशत गोदाम पी.पी.पी. मोड पर संचालन के लिए ऑरिगो कॉमोडिटीज और श्री शुभम् लॉजिस्टिक को सौंप रखे हैं। इनमें से श्री शुभम् लॉजिस्टिक के गोदामों में रखी जाने वाली कृषि उपज का पर्याप्त बीमा नहीं कराया हुआ, जबकि ऑरिगो कॉमोडिटीज का इंश्योरेंस तो गत 2 अक्टूबर से ही खत्म हो चुका है, जिसे अभी तक रिव्यू भी नहीं कराया गया है। ऐसे में इन गोदामों

मामला प्रदेश में अक्टूबर माह से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद और भंडारण से जुड़ा है

■ दरअसल राजफेड ने 18 अक्टूबर से खरीफ की फसलें खरीदना शुरू की, परंतु फसलों के भंडारण से संबंधित "मूवमेंट प्लान" को बनाने से पूर्व ना तो भंडारण निगम के अफसरों को सूचना दी गई और ना ही गोदामों की क्षमता, बीमा, सुविधा व खाली जगह के बारे में कोई जानकारी ली।

■ ऐसे में किसानों से खरीदी गई यह उपज भंडारण निगम के उन गोदामों में भी पहुंचेगी, जिनका संचालन ऑरिगो कॉमोडिटीज और श्री शुभम् लॉजिस्टिक कंपनी पी.पी.पी. मोड पर करती है, कृषि उपज रखने के लिए। इन कंपनियों ने बीमा तक नहीं करवा रखा है।

■ राजफेड की अनदेखी के कारण दलहन-तिलहन का यह स्टॉक उन गोदामों में भी जायेगा, जहां सुरक्षा, इंश्योरेंस कवर और भरपूर क्षमता नहीं है। ऐसे में आनन-फानन में निजी गोदामों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे सीधा-सीधा बाजार भाव की वृद्धि होगी।

में रखी जाने वाली हजारों करोड़ों रु. की

कृषि उपज अगर किसी दुर्घटना में नष्ट

होती है अथवा चोरी होती है या सड़ती

जल्दी आयेगी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी व फार्मा पॉलिसी-मुख्यमंत्री

राइजिंग राजस्थान हैल्थ प्री-समिट में 16,176 करोड़ के एम.ओ.यू. साइन हुए

जयपुर, 14 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आज राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गए। आज किए गए एम.ओ.यू. के साथ ही

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस प्री-समिट में 2,157 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. आयुष क्षेत्र में हुए।



राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 16,176 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए।

“राइजिंग राजस्थान” ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बैनर तले स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

आज किए गये एम.ओ.यू. में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एम.ओ.यू. हुए, जबकि आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपये के निवेश एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करके हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम न केवल न केवल एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं बल्कि अगले 3-4 वर्षों में उन्हें घरातल पर भी उतारने जा रहे हैं।

आयुष क्षेत्र में हुए 2,157 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में एम.ओ.यू. किए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 28,000 करोड़ रुपये

आवंटित किया गया है। सरकार, राज्य की चिकित्सा पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने के लिए नई फार्मा पॉलिसी और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी भी लॉन्च करने जा रही हैं। आज किए गए एम.ओ.यू. के जरिए निवेशकों ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, सिरौही सहित राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में फार्मा इकाइयां, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी और आयुर्वेद कॉलेज, आयुष अनुसंधान पंचकर्म केंद्र, उन्नत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा

संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

इस अवसर पर मौजूद राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयदेव सिंह खोवसर ने कहा, ये नये निवेश न केवल राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नए स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर लाएंगे, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

कार्यक्रम के अंत में राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरश्री कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

आप के महेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेलना पड़ेगा। जिसका सीधा असर इन कृषि उपज के बाजार भावों में भी तेजी के तौर पर दिखेगा। पाठकों को बता दें कि, गोदामों में कृषि उपज रखते समय कई तरह की जांच होती है, जिनमें वजन मापना, नमी के स्तर की जांच, उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, आपात स्थिति में कृषि उपज को सुरक्षित अन्न शिफ्ट करने के इंतजाम, आगजनी अथवा अन्य हादसों से निपटने के उपाय, कीट सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। इन मापदण्डों की जांच के बाद ही गोदामों को कृषि उपज रखने के लिए सही माना जाता है।

गौवंश तस्कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से संबंधित आरोप है। आरोपी खान का आपराधिक इतिहास उसे एक आदतन अपराधी बनाता है। ऐसे में जमानत पर छोटे रहने पर उससे ना केवल सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा है, बल्कि गौवंश तस्करों में उसके अपराध का सिलसिला भी जारी रह सकता है। राज्य सरकार गौवंश तस्करों को रोकने के लिए उपाय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आरोपी की जमानत रद्द करता है तो इससे पशु क्रूरता व अवैध परिवहन मामलों के आरोपियों में कानून की सख्त कार्रवाई स्थापित होगी। इसलिए अदालत आरोपी को दी जमानत आदेश पर पुनर्विचार करें।

कर्नाटक में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुहियत शुरु की। इसीलिए वे बार-बार केस कर रहे हैं।

मई 2023 में कांग्रेस 135 सीटों का शानदार बहुमत अर्जित कर कर्नाटक की सत्ता में आई है तब से ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच नेतृत्व के मुद्दे पर जंग छिड़े होने की अफवाह चल रही है। अभी तक सरकार आराम से चल रही है। सार्वजनिक रूप से दोनों नेता एकजुट दिख रहे हैं और शिव कुमार ने मुख्यमंत्री को भाजपा के लिए किए गए दावे का भी समर्थन किया है।

उन्होंने बैंगलूर में कहा कि रिश्त की कथित पेशकश भाजपा के “ऑपरेशन लोटस” का हिस्सा थी। इस पर कड़ा विरोध जाता है हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.बाय. विजयेन्द्र ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अपने आरोपों को साबित करें। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर परोसा नहीं है और वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आत्मीयता है, आत्मीयता के जांच एजेंसियां हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जनता को यह बताना कि रिश्त की पेशकश किसन की थी वरना आपका बयान एक बचकाने राजनैतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सिद्धार्थमैया ने यह आरोप अपनी पार्टी व विधायकों पर नियंत्रण रखने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए लगाए हैं।

इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर गुब्बारा को संहति व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि, याचिका में को से अनुरोध किया गया

प्रदूषण के कारण दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद

सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाएँ चलाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण पर लगी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली, 14 नवंबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। अब पहली से पांचवी तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा “बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे और अगले निर्देश तक जारी रखेंगे।” दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए और बच्चों के माता-पिता को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।

इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर गुब्बारा को संहति व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि, याचिका में को से अनुरोध किया गया

था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाये इसलिए याचिका को तत्काल सुचीबद्ध किया जाए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर संहति जता दी।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने के आदेश में कहा गया है, “दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 5 तक के

बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।”

दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी बताया गया है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप-3 लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली और एनसीआर में ए.क्यू.आई. 401-450 के बीच है। शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 नवंबर, 2024 की सुबह 8 बजे से जीआरपीओ-गंधी वायु गुणवत्ता के चरण के तहत सभी उपाय लागू किए जाएंगे। अब साल 2017 से पहले खरीदे गए वाहन, जो बीएस-3 या उससे कम मानदंड के हैं, उनके उपयोग पर बंद लगा दिया गया है।

ट्रम्प की, सरकारी खर्च कम करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1970 के दशक में केरल से संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे लेकिन दोनों “जन्मजात श्वेत अमेरिकी” नहीं हैं। मस्क दक्षिण अफ्रीका से हैं और रामास्वामी भारतीय मूल के हैं।

यदि ये दोनों व्यक्ति एक अच्छे ज्ञानी और शिक्षित पृष्ठभूमि से आते हैं, तो डॉनल्ड ट्रम्प किताबों और अध्ययन की दुनिया में लगभग अजनबी प्रतीत होते हैं। उनका जीवन संपत्ति और खर्च, जोखिमपूर्ण आदतों और चालबाजियों से

भरा हुआ रहा है। उन्हें अमेरिकी अदालत द्वारा दोषी भी ठहराया गया है।

सरकारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके चयन से उदार अमेरिकी नागरिकों और आम जनता को सहन हो सकती है। मस्क का यह दावा है कि उनके प्रस्तावों से अमेरिका के 6.5 ट्रिलियन डॉलर के बजट में से 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती की जा सकती है। इससे सरकारी एजेंसियों और विभागों से लाखों लोग सीधे बाहर हो जाएंगे और अन्य कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।

सरकार का आकार घटाने से अमेरिकी सामाजिक क्षेत्र के बजट के साथ-साथ उसकी विशाल सैन्य बजट में भी कटौती हो सकती है, विशेषज्ञों का कहना है। सरकार के आकार को घटाने के प्रयासों का विभिन्न प्रकार से असर हो सकता है, जिसका उन लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा सकता है जो सरकारी अभिजात्य वर्ग में हैं या स्थापित राजनीतिज्ञ हैं। सबसे बड़ा विरोध राजनीतिक वर्ग से हो ही सकता है। राजनेता संघीय बजट पास करते हैं और

प्रशासनिक राज्य का वह हिस्सा जो वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित करता है, वह कांग्रेस है। राजनीतिक वर्ग इन अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। विधानमंडल बजट पास करने पर जोर देगा और मस्क तथा रामास्वामी जैसे विशेषज्ञों के हस्तक्षेप को तबज्जो नहीं देगा।

बाल मुकुंदाचार्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवाद में अधिकता असलम ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को शाम के समय बालमुकुंदाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति, इमाम बारगाहा में जबरन घुस गए और अभद्रता करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और पदर्शनशील महिलाएं भयभीत हो गईं।

वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खीले की कहा तो विधायक बालमुकुंदाचार्य ने उन्हें आतंकी सहित अन्य अपशब्द बोले। इसके अलावा विधायक ने वक्फ बोर्ड की ओर से लगाए वक्फ संपत्ति के बोर्ड पर एतराज किया।

परिवाद में कहा गया कि विधायक ने अपने सहयोगी के माध्यम से घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया, ताकि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़े और परिवादी के धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा खराब हो। इस संबंध में शहर के ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को साक्ष्य पेश करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने 26 हजार प्राइमरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गए हैं। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार इस संकट से कैसे निपटेंगी। सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी चली गई है, जो लोग इन नियुक्तियों को चुनौती दे रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी संख्या बहुत बढ़ी है। अदालत के निर्णय ने दिखा दिया है कि तृणमूल नेता कितने भ्रष्ट रहे हैं। विशेष रूप से, क्वॉकि, तृणमूल

कांग्रेस ने, इस निर्णय को टालने और रद्द करवाने के लिए हर तरह की कोशिश की थी। पार्टी ने भारी भरकम राशि खर्च करके हाई प्रोफाइल वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सेवाने ली थीं। सभी विपक्षी पार्टियों ने, शिक्षकों की नियुक्ति बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती देने के सरकार के निर्णय की भारी आलोचना की थी। अब सरकारी की स्थिति बहुत खराब है और विपक्षी पार्टियां हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई हैं।

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण 3,209 मीटर लम्बी टी-वन सुरंग भी पूरी बन गई है। इसके निर्माण में काफी भौगोलिक व तकनीकी चुनौतियां आई थीं। अब यहां परतियां बिछाने का काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व में

घोषणा की थी कि यू.एस.बी.आर.एल. (उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला) दिसम्बर 2023 या जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब चूकित टी-वन की बाधा पार हो गई है तो अगले वर्ष के आरंभ तक ट्रंक चालू हो जाएगा। पर अब लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट की नई बहस छिड़ गई है प्रोजेक्ट पर और देरी हो सकती है।



सत्यमेव जयते
Government of Rajasthan



**RISINGTM
RAJASTHAN**
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR

REPLETE • RESPONSIBLE • READY



REGISTER NOW
rising.rajasthan.gov.in



SH. BHAJAN LAL SHARMA
Hon'ble Chief Minister, Rajasthan



SH. NARENDRA MODI
Hon'ble Prime Minister